

परसपेक्टवि: महिला नेतृत्व में विकास

प्रलिमिंस के लयि:

[जी-20](#), [समावेशी विकास](#), [सतत विकास](#), [मौद्रकि नीति](#), [राजकोषीय नीति](#), [महिला आरक्षण अधनियम](#), [सर्टैंड-अप इंडिया](#), [PM मुद्रा योजना](#), [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ](#), [PM जन धन योजना](#), [राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन](#), [PM आवास योजना](#), [प्रसूति अवकाश](#) ।

मेन्स के लयि:

महिला नेतृत्व में विकास के बारे में, लैंगकिता का भारत की प्राथमकिताओं में शीर्ष पर होना, भारत में महिला नेतृत्व में विकास के मार्ग में चुनौतियाँ, महिला नेतृत्व में विकास का भारतीय दृष्टिकोण ।

संदर्भ क्या है?

हाल ही में भारत ने अपनी [जी-20](#) अध्यक्षता के दौरान समावेशी विकास, [सतत विकास लक्ष्यों](#) की प्राप्ति में प्रगति, पर्यावरण के अनुकूल विकास, तकनीकी नवाचार और बहुपक्षीय संस्थानों के पुनर्गठन के साथ-साथ "महिला नेतृत्व में विकास" को छह केंद्रीय बडुओं के रूप में नामति कथिा, यह भारत के भीतर एक प्रमुख नीतगित मुद्दे के रूप में लैंगकि समानता को संबोधति करने के स्थायी महत्त्व की मान्यता का प्रतीक बना ।

महिला नेतृत्व में विकास क्या है?

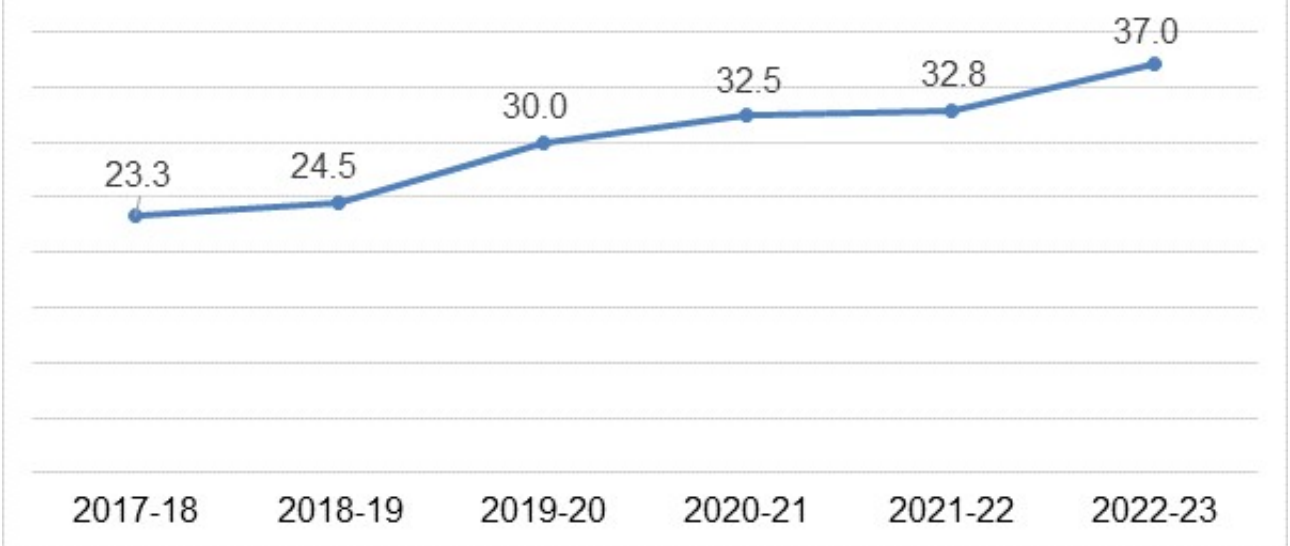
- "महिलाओं के नेतृत्व में विकास" एक विकास दृष्टिकोण को संदर्भति करता है, जसिमें महिलाएँ अग्रणी भूमकि नभित्ती हैं और कसिी समाज या समुदाय की आर्थकि, सामाजकि तथा राजनीतिक प्रगति में सक्रयि भूमकि नभित्ती हैं ।
- महिला-नेतृत्व में विकास के तहत महिलाएँ केवल विकास की लाभार्थी नहीं हैं, बल्कवि नेतृत्वकर्त्ता के रूप में विकास का एजेंडा तय करने और विकास योजना के नरिमाण तथा नरिणयन में भागीदारी करती हैं ।
- इसमें सामाजकि-आर्थकि विकास और SDG की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लयि महिलाओं को आगे भी अग्रणी पदों में नयिोजति करने पर ध्यान केंद्रति करना है ।
- इस दृष्टिकोण का उद्देश्य लैंगकि समानता के महत्त्व को पहचानने के साथ उन बाधाओं को दूर करना है जिन्होंने ऐतहिसकि रूप से विकास के वभिन्न पहलुओं में महिलाओं की भागीदारी और योगदान को सीमति कर दयिा है ।

लैंगकिता भारत की प्राथमकिताओं में शीर्ष पर क्यों है?

- व्यापक लैंगकि अंतर: [ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023](#) में भारत को 146 देशों में से 127वाँ स्थान दयिा गया था और कार्यबल से "महिलाओं के अनुपस्थति होने की" (Missing Women) सार्वकालकि समस्या का सामना करता है, जो एक बड़ी समस्या है ।
- समावेशी नरिणय-नरिमाण: महिलाओं के नेतृत्व में विकास समावेशी नरिणय-नरिमाण संरचनाओं को बढ़ावा देता है जसिमें सामुदायकि योजना, संसाधन आवंटन और नीति नरिमाण में महिलाओं को शामिल कयिा जाता है । यह समावेशिता समुदाय के भीतर वविधि आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को संबोधति करने में सहायता करती है ।
- सामुदायकि विकास: जब महिलाओं की संसाधनों तक पहुँच होती है, तो वे पुरुषों की तुलना में परिवार और समुदायों की शकिषा एवं स्वास्थ्य में अधिक नविश करती हैं । [पंचायती राज संस्थाओं](#) में महिलाओं ने वभिन्न सामुदायकि विकास परयोजनाओं को शुरु करने के साथ उन्हें कार्यान्वति कयिा है । इसमें जल प्रबंधन, स्वच्छता, ग्रामीण बुनयिादी ढाँचे और गरीबी उन्मूलन से संबंधति पहल शामिल हैं ।
- सतत विकास: महिलाओं के नेतृत्व में विकास को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाता है । पर्यावरण के अनुकूल और सामाजकि रूप से ज़मिेदार प्रथाओं को बढ़ावा देकर ये पहल समुदाय के दीर्घकालकि कल्याण में योगदान करती हैं ।
- गुणक प्रभाव: भारतीय अर्थव्यवस्था पर महिला नेतृत्व में विकास का गुणक प्रभाव पड़ता है । [मैकनिसे](#) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में 18% तक का इज़ाफा कर सकता है, बशर्ते कविह देश में महिला कार्यबल की भागीदारी में सुधार करलैंगकि समानता के अंतर को खतम करे ।

//

Female Labour Force Participation Rate
(%, 15 Years and above, Usual Status)



महिला नेतृत्व में विकास को लेकर प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **गहरी जड़ें जमा चुकी पतिसत्ता:** भारत में पतिसत्तात्मक मानदंड और सामाजिक संरचनाएँ गहरी जड़ें जमा चुकी हैं जो महिला सशक्तीकरण और नेतृत्व में बाधा बनती हैं। इन सांस्कृतिक दृष्टिकोणों और व्यवहारों को बदलना एक बड़ी चुनौती है।
- **लगा आधारति हिसा:** भारत में महिलाओं के खिलाफ हिसा की दर दुनिया में सबसे अधिक है। [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो \(NCRB\)](#) के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले सामने आए, जिनमें से 32,033 मामले बलात्कार के थे।
- **संसाधन आवंटन:** महिलाओं के नेतृत्व में विकास पहलों के लिये संसाधनों का आवंटन और यह सुनिश्चित करना कठिनाई है। प्रशासनिक अक्षमताओं और भ्रष्टाचार के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
 - कृषि जनगणना से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 में महिला भूमि मालिकों की संख्या केवल 13.9% थी।
- **राजनीतिक अल्प-प्रतिनिधित्व (Political Underrepresentation):** स्थानीय स्तर सहित राजनीतिक भूमिकाओं में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। महिलाओं की अधिक राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना एक चुनौती है।
 - भारत की संसद में केवल 82 महिला- लोकसभा में (15.2%) और राज्यसभा में (13%) सदस्य हैं।
- **डेटा संग्रह और विश्लेषण:** महिलाओं की स्थिति और नीतियों के प्रभाव पर विश्वसनीय डेटा एकत्र करना और विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे प्रगति को मापना मुश्किल हो जाता है।
- **कानूनी प्रवर्तन:** हालाँकि भारत ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये विभिन्न कानून बनाए हैं, लेकिन इन कानूनों का कार्यान्वयन असंगत हो सकता है, जो न्याय और जवाबदेही के लिये चुनौती बन सकता है।

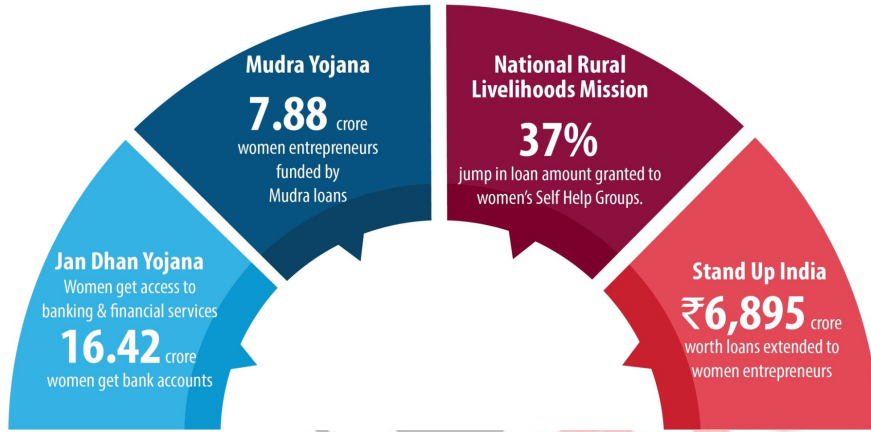
महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलें क्या हैं?

- [महिला आरक्षण अधिनियम](#)
- [स्टैंड-अप इंडिया](#)
- [PM मुद्रा योजना](#)
- [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ](#)
- [PM जनधन योजना](#)
- [राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन](#)
- [PM आवास योजना](#)
- [प्रसूति अवकाश](#)



India is moving from Women Development to Women-Led Development

Funding the aspirations of women entrepreneurs



आगे की राह क्या होनी चाहिये?

- **नेतृत्व और नरिणय लेना:** भारत को ज़मीनी स्तर पर महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ राजनीतिक प्रणालियों और शासन में महिलाओं के नेतृत्व एवं सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिये।
- **शिक्षा और कौशल:** भारत को विशेष रूप से STEM क्षेत्रों में महिलाओं के लिये शिक्षा में नविश और पहुँच बढ़ाने पर ज़ोर देना चाहिये।
- **महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना:** महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और महिलाओं के स्वामित्व वाले तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) का समर्थन करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- **अदृश्य काम को पहचानना:** घरेलू कार्यों की पहचान एवं उन्हें मान्यता देकर अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा में नविश करने तथा सकल घरेलू उत्पाद को फरि से परभाषित करने की आवश्यकता है।
- **जलवायु और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका:** भारत को जलवायु संबंधी लचीलेपन के साथ पारस्थितिकी तंत्र के नरिमाण में महिलाओं की भागीदारी के महत्त्व पर प्रकाश डालना चाहिये। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण से निपटने में महिलाओं की भूमिका को पहचानना और बढ़ावा देना।
- **बदलती मानसिकता:** भारत में महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करने के लिये समाज की मानसिकता को बदलना आवश्यक है। महिलाओं के नेतृत्व को महत्त्व देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिये जागरूकता का प्रसार करना और शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है।

